

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2896**  
जिसका उत्तर 6 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।  
15 श्रावण, 1947 (शक)

**विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना**

**2896. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के अंतर्गत इसके प्रारंभ वर्ष से अब तक प्रदान की गई पीएचडी फेलोशिप की कुल आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार संख्या कितनी है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है और अवसंरचना सहायता, शोध अनुदान और अध्येताओं को प्रदान की गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस योजना से लाभान्वित संस्थानों और शोध केंद्रों का ब्यौरा क्या है और उनके विषयगत फोकस क्षेत्र और प्रमुख शोध परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त पीएचडी अध्येताओं के रोजगार और शोध परिणामों का ब्यौरा क्या है, और शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी संस्थानों में उनकी नियुक्ति का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार की उक्त योजना को बढ़ाने या विस्तार करने की कोई योजना है, जिसमें उभरते शोध क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण, कवरेज या विशेष प्रोत्साहन बढ़ाना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (ङ)** सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं द्वारा सेमीकंडक्टर, एआई, उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों आदि जैसे उभरते क्षेत्रों सहित संपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए प्रतिभा और क्षमताओं का सृजन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना इस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है।

इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के ज्ञान-गहन क्षेत्रों में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश में पीएचडी की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, पीएचडी विद्वानों और युवा संकाय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कर रहे हैं। यह योजना संस्थानों को अनुसंधान अवसंरचना सहायता भी प्रदान करती है। यह योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है।

योजना का चरण-1 वर्ष 2014 में 9 वर्षों की अवधि के लिए 466.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। देश भर में कुल 1,075 पीएचडी फेलोशिप प्रदान की गई। पीएचडी फेलोशिप का राज्य-वार वितरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

योजना का चरण- ॥ वर्ष 2021 में 9 वर्षों की अवधि के लिए 481.93 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। अब तक कुल 561 पीएचडी फेलोशिप प्रदान की जा चुकी हैं। पीएचडी फेलोशिप का राज्य-वार वितरण अनुबंध-॥ में दिया गया है।

दोनों चरणों के तहत विभिन्न बजट मदों में धनराशि का वर्षावार विवरण योजना पोर्टल: <https://phd.dic.gov.in/finance-details> पर उपलब्ध है।

इस योजना ने देश भर में 171 संस्थानों को सहायता प्रदान की है, जिनमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय और पीएचडी प्रदान करने की अनुमति वाले कॉलेज शामिल हैं।

इस योजना के तहत पीएचडी स्कॉलर्स इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकग्निशन, 3डी प्रिंटिंग, 5जी कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, डिस्ट्रिब्यूटेड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, ग्रीन एंड सस्टेनेबल आईसीटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं। इस योजना के तहत 4,063 शोध पत्र प्रकाशित और 90 पेटेंट दायर किए गए हैं, जिनमें 20 स्वीकृत पेटेंट शामिल हैं। विद्वानों ने शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी संस्थानों में प्लेसमेंट पाई है, जिससे देश के नवाचार इकोसिस्टम में योगदान मिला है।

उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को और बढ़ावा देने के लिए, इस योजना में युवा संकाय अनुसंधान फेलोशिप के प्रावधान भी शामिल हैं, जो अकादमिक संस्थानों में युवा संकाय को उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान करने हेतु सक्षम बनाते हैं।

\*\*\*\*\*

## चरण-। में विशेष्वरैया पीएचडी योजना के तहत पीएचडी फैलोशिप की राज्य-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएचडी फैलोशिप की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	10
2	अरुणाचल प्रदेश	11
3	অসম	49
4	बिहार	54
5	चंडीगढ़	11
6	दिल्ली	136
7	गोवा	13
8	गुजरात	25
9	हरियाणा	8
10	हिमाचल प्रदेश	27
11	जम्मू और कश्मीर	5
12	झारखण्ड	3
13	कर्नाटक	97
14	केरल	9
15	मध्य प्रदेश	43
16	महाराष्ट्र	84
17	मेघालय	12
18	मिजोरम	0
19	ओडिशा	11
20	पुडुचेरी	8
21	ਪंजाब	34
22	राजस्थान	37
23	सिक्किम	5
24	तमिलनाडु	100
25	तेलंगाना	80
26	त्रिपुरा	3
27	उत्तर प्रदेश	83
28	उत्तराखण्ड	21
29	पश्चिम बंगाल	96
	<b>कुल</b>	<b>1075</b>

## चरण- II में विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के तहत पीएचडी फैलोशिप की राज्यवार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फैलोशिप की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16
2	अरुणाचल प्रदेश	10
3	असम	18
4	बिहार	9
5	चंडीगढ़	8
6	छत्तीसगढ़	11
7	दिल्ली	46
8	गोवा	6
9	गुजरात	22
10	हरियाणा	19
11	हिमाचल प्रदेश	11
12	जम्मू और कश्मीर	14
13	झारखण्ड	13
14	कर्नाटक	29
15	केरल	26
16	मध्य प्रदेश	39
17	महाराष्ट्र	20
18	मणिपुर	8
19	मेघालय	11
20	मिजोरम	6
21	ओडिशा	20
22	पुडुचेरी	10
23	पंजाब	40
24	राजस्थान	22
25	सिक्किम	2
26	तमिलनाडु	38
27	तेलंगाना	14
28	त्रिपुरा	5
29	उत्तर प्रदेश	32
30	उत्तराखण्ड	13
31	पश्चिम बंगाल	23
	<b>कुल</b>	<b>561</b>

\*\*\*\*\*